Page No.
Date

MATA SUNDRI COLLEGE FOR WOMEN

Topic :- What is budget? what is budgetary Process?

Subject :- Legislative Support.

Submitted By :-

Name :- Shahin
College roll no :- BAP/20/169
Section :- A
Course :- B.A (Prog.)- 501
Semester :- iii (3rd)

Submitted to :- DR. Moitri Dey.

Submission Date :-

ACKNOWLEDGEMENT

Primarily I would thank God for being able to complete this Assignment with Success. Then I would like to thanks my legisative support teacher Dr Moitri Dey whose valuable Guidance has been the success her suggestion and her instructions has served As the Major contributor towards the completion of the Assignment

Then I would like to thank my Parents and friends who have help me with their valuable suggestions and Guidance has been helpful in various phase of the completion of the Assignment

Last but not the least I would like to thank you class mates who have helped me a lot.

Shahin

BIBLIOGRAPHY

I have taken all these informations from Google, Books and classnotes.
Help from Internet fallowing websites links Have been used in the Completion of this Assignment :-

* www. wikipedia . arg
* www. warwick . ac. vk
* www. youmatter. world

Book is used to have an Idea
- Legislative Support
- class notes.
- Suitable and related PDFs

Page No.
Date

QUESTION - What is the budget? What is the budgetary Process in India?

बजट क्या है? भारत मे बजट की प्रक्रिया क्या है?

ANSWER - बजट क्या है:- एक बजट एक निर्दिष्ट भविष्य की अवधि मे राजस्व और व्यय का अनुमान है और आमतौर पर आवधिक आधार पर संकलित और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। बजट एक व्यक्ति, लोगो के समूह एक व्यवसाय, एक सरकार या किसी अन्य चीज के लिए बनाया जा सकता है जो पैसा बनाता है और खर्च करता है।

अपने मासिक खर्चों का प्रबंधन करने के लिए, जीवन की अप्रत्याशित घटनाओ के लिए तैयार रहे और बिना कर्ज के बड़ी-बड़ी वस्तुओ को वहन करने मे सक्षम होने के लिए बजट बनाना महत्वपूर्ण है।

* बजट की समझ (Understanding budgeting)

बजट एक सूक्ष्म आर्थिक अवधारणा है जो व्यापार बंद को दर्शाता है जब एक अच्छा दूसरे के लिए आदान-प्रदान किया जाता है। नीचे की रेखा के संदर्भ मे - या इस व्यापार-बंद के अंतिम परिणाम - एक अधिशेष बजट का मतलब है की लाभ प्रतिशत है।

एक संतुलन बजट का मतलब है की राजस्व समान खर्चों की उम्मीद है, और घाटे के बजट का मतलब है की खर्च राजस्व से अधिक हो जाएगा।

→ कॉर्पोरेट बजट :- बजट किसी भी व्यवसाय को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से चलाने का एक अभिन्न अंग है।

→ बजट Budget :- आगामी बजट अवधि के लिए अनुमान स्थापित करके प्रक्रिया शुरू होती है। ये धारणाए अनुमानित बिक्री प्रवृत्तियां, लागत प्रवृत्तियां और बजार, उद्योग या क्षेत्र के समग्र आर्थिक दृष्टिकोण से संबंधित है। संभावित खर्चों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट कारको का ध्यान दिया जाता है और उनकी निगरानी की जाती है।

बजट को एक पैकेट मे प्रकाशित किया जाता है जो इसे विकसित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानको और प्रक्रियाओ की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमे बाजार के बारे मे धारणाएँ, छूट प्रदान करने वाले विक्रताओ के साथ प्रमुख संबंध और कुल गणना कैसे की जाती है इसकी व्याख्या शामिल है।

* बजट एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल किसी देश की आर्थिक क्रिया को दर्शाता है बल्कि यह सभी क्रियाओ को दर्शाता है बजट के वित्तियता के अलावा भी कई उपयोग है इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण

Page No. 3

माना जाता है।
* बजट हमारी निति को, कार्यो को एक मंच पर दर्शाता है। इससे यह भी पता चलता है की किस प्रकार हमारा कर (Tax) इस्तेमाल हो रहा है।
- सरकार Government का उद्देश्य क्या है। तथा पिछले बजट की भी तुलना कि जाती है।
- बजट समाज की असीमित इच्छाओ का शस्त्र है तथा इससे पता चलता की हम कैसे कैसे अपने साधनो को संपूर्ण तथा समान रूप से बाट सके।

* बजट अपनी हर stage (स्तर) पर यही चाहता है की हम अपने सभी संसाधनो को संपूर्ण तथा समान रूप से बाँट कर सके। तथा यह कार्य न्यायपूर्वक पूर्ण हो सके।
* दूसरे शब्दो मे बजट सरकार का वह शस्त्र है जिससे साधनो को समान संपूर्ण तथा न्यायपूर्वक ढंग से बांटा जाता है। यह केवल वित्तिय संबन्धित नही होता।

-> नीति को किस प्रकार लागू करना है यह भी बजट बताता है। क्योंकि नीति बनाने के लिए योजना बनाई जाती है तथा योजना एक बजट की सहायता से ही पूर्ण होती है
-> बजट के ज़रिए ही हम मूल्यांकन करते है सरकार के कार्यो का, सरकार Government किस प्रकार से कार्य करती है, इन सबका पता भी हमे बजट के द्वारा चलता है। बजट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

→ हमारे चुने गए प्रतिनिधियो को जवाब देह भी बनाता है बजट
बजट एक साधारण दस्तावेज नही है यह एक विशाल दस्तावेज है

" Budget is not simple Document it is huge document."

* रेमो स्टार्म के अनुसार :-
बजट एक ऐसा परिपत्र है जिसमे सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक घोषनाए प्रस्तुत की जाती है।

→ इस प्रकार से बजट एक तुलनात्मक व्यवस्था है जिसमे एक ओर धन के आगमन की व्यवस्था की जाती है तथा दूसरी ओर विभिन्न मदो पर धन के व्यय का आंकलन किया जाता है बजट का अर्थ सरकार को सीमित रूप से न देखकर इसे इतिहास की भी पृष्ठभूमि के साथ वर्तमान को व्यवस्थित करते हुए भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए।

* भारत के संविधान मे बजट शब्द कही भी उल्लेखित नही है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 112 मे कहा गया है की राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बंध मे संसद के दोनो सदनो के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण रखेगा (Annual Financial Statement) इसमे वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियो और खर्च का विवरण होता

है जो 1st April से आरंभ होकर 31st मार्च तक होता है।
बजट मे निम्नलिखित शामिल है।-

* 1). राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियाँ
2). राजस्व बढ़ाने के उपाय एवं साधन
3). खर्च का अनुमान
4.) वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्चे का विवरण
5). आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति कर व्यवस्था, खर्च की योजना एवं नयी परियोजना।

बजट के सिद्धांत (Principles of Budgeting)

बजट चाहे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाए चाहे राज्य सरकार द्वारा निर्मित हो सभी स्थानो पर बजट के कतिपय सामान्य सिद्धांत ऐसे है जिनका पालन किया जाता है ये सिद्धांत इस प्रकार है

1). **बजट की नियमितता** :- जिसके अन्तर्गत प्रति वर्ष जहा तक हो सके बजट का अनुमान एक निश्चित समय अवधि के दौरान लगा लेना चाहिए

2). **स्पष्टता** :- बजट के प्रति एक भाग मे वर्णित तथ्य पूर्णतया स्पष्ट होने चाहिए क्योंकि यह उलझाव संकट उत्पन्न करती है।

3). **एकता और व्यापकता** :- यह दर्शाती है सभी आय-व्यय विवरण एकीकृत रूप से वर्णित हो तथा उनमे सम्पूर्ण राजकोषीय कार्यक्रमों का सारांश प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4). **बजट का संतुलन** :- संतुलित बजट से तात्पर्य यह है कि अनुमानित व्यय अनुमानित आय से अधिक नहीं होना चाहिए।

5). **बजट में लोचशीलता** :- अर्थात बजट केवल अनुमानित होता है व उसके अनुमानों में संशोधन की संभावना बनी रहती है

6). **बजट की सत्यता तथा शुद्धता** :- बजट जैसा दर्शाया जाए वैसे ही क्रियान्वित होना चाहिए साथ ही बताए गए राजस्व प्राप्ति के आंकड़े पूर्ण रूप से शुद्ध होने चाहिए

7). **अवसान का नियम** :- इसका अभिप्राय की एक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान और बजट राशी की समाप्ति पर खत्म हो जाता है वर्ष के अंत में बची हुई राशी को भविष्य में व्यय करने के लिए बचाकर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है

8). **नकद आधार** :- बजट के वर्ष के मध्य नकद रूप में प्राप्त होने वाली आमदनी तथा किए जाने वाले व्यय के आधार पर बनाया जाता है

9). **बजट मे लेखा विधि** :- इसके अनुसार बजट मैनुअल के नियमों का पालन होना चाहिए ताकि उपर्युक्त वर्णित सिद्धांतो को व्यवहारिक रूप मिल सके

10). **प्रचार** :- बजट को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए।

बजट के विभिन्न रूप

1. (Performance Budgeting)

* 1. निष्पादन बजट (भारत में परंपरागत बजट प्रणाली को अपनाया गया जिससे कि संसद के द्वारा बजट पर आवश्यक नियंत्रण रखा जाता है परंतु 1950 के दशक में बजट में कुशलता पर भी ध्यान दिया जाने लगा। इसी कार्यकाल में निष्पादन बजट का प्रयोग हूवर कमीशन Hoover Commission 1949 द्वारा अमेरिका में किया गया। इस आयोग के द्वारा अमेरिका में निष्पादन बजट को अपनाने का सुझाव दिया गया भारत में पारम्परिक बजट का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना तथा विकास कार्यों को अंजाम देना है न की तीव्र गति से विकास। परिणाम स्वरूप पारम्परिक बजट की यह पद्धति स्वतंत्र भारत की समस्याओं को सुलझाने तथा विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रही। यही कारण है कि भारत यह निष्पादन बजट Performance Budget की आवश्यकता तथा महत्व को स्वीकार किया गया तथा इसे पारम्परागत बजट के पूरक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है

* 2. शुन्य आधारित बजट (Zero Base Budgeting)
इस बजट के 2 प्रमुख कारण है।

क. देश के बजट में निरंतर पाया जाना वाला घाटा

ख. निष्पादन बजट प्रणाली का सफल क्रियान्वयन न हो पाना।

उपरोक्त दोनो बातो ने इस बात पर जोर दिया है की देश के बजट में लगातार

बढ़ते व्यय पर अंकुश लगाने के लिए व्यय में कटौती करना आवश्यक है। यह प्रणाली विगत वर्षों में किए गए व्ययों को विचार नहीं करती और न ही विगत वर्षों के व्ययों को आगे वर्ष के लिए प्रयुक्त करती है बल्कि यह प्रणाली इस बात पर जोर देती है कि व्यय किया जाए या नहीं?

Zero Base Budgeting के लाभ निम्नलिखित हैं

1. इससे गैर-महत्वपूर्ण कार्यक्रम समाप्त हो जाते हैं या उनकी संख्या में कमी आती है
2. इससे कार्यक्रम की कुशलता में वृद्धि आती है
3. इससे व्यय में वृद्धि पर रोक लगती है
4. इससे कार्यक्रम / योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन होता है जिससे योजना में मितव्ययता आती है
5. इसके द्वारा सीमित संसाधनों का तार्किक आधार पर उपयोग किया जाता है।

*3. कार्यक्रम बजट (Programme Budgeting)

कार्यक्रम बजट का जन्म भी अमेरिका में ही हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा 1965 में कार्यक्रम बजट को अपनाया परन्तु यह बजट अमेरिका में अधिक समय तक लागू नहीं रहा तथा 1971 में अमेरिका में इसे खत्म कर दिया गया। कार्यक्रम बजट प्रणाली में योजना कार्यक्रम व बजट को एक साथ मिला दिया जाता है। इसमें प्रभावशाली को उसकी कुशलता से अधिक महत्व दिया जाता है।

4. लक्ष्य आधारित बजट (Target Based Budgeting) इसमें पहले की बजट प्रणाली जैसी निष्पादन, तथा शून्य आधारित बजट तथा कार्यक्रम बजट के लक्षण विद्यमान होते हैं। इस बजट प्रणाली में केन्द्रीय प्रशासन को किसी कार्यक्रम के उद्देश्य व उस पर होने वाले व्यय का निर्धारण करने का अधिकार रहता है। इसकी ओर-यहाँ परंपरागत बजट नीचे से ऊपर की तरफ होता है, वही इसकी ओर लक्ष्य आधारित बजट में बजट निर्माण केंद्र से स्थानीय विभाग की ओर होता है।

5. परिणाम बजट (Outcome Budgeting) परिणाम बजट में मुख्यतः इस तत्व पर ध्यान दिया जाता है कि किसी कार्यक्रम पर कितना धन व्यय किया जाता है तथा इसके परिणाम इस व्यय के अनुरूप है या नहीं। परिणाम बजट मंत्रालयों और विभागों के कार्य प्रदर्शन में एक मापक का भी काम करता है, जिससे संगठनात्मक प्रक्रिया, कार्यक्रमों के मूल्यांकन और परिणामों को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है इससे यह निश्चित हो जाता है कि परिणाम बजट (Outcome Budget) के जरिए विकास कार्यक्रमों को और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है तथा इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की सही-सही जानकारी भी मिल जाती है।

6. जेण्डर आधारित बजट (Gender Budgeting)
हमारे देश में महिला अधिकारिता और महिला सशक्तीकरण की दिशा में बजट के योगदान को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005-2006 के बजट पहली बार व्यवहारिक तौर पर जेण्डर बजटिंग की शुरुआत की गई और वर्ष 2006-2007 में इस व्यवस्था को आंशिक कारगर तरीके से लागू करने पर बल दिया गया

Rail Budget
रेल बजट

तकनीकी अर्थ में यह रेलवे बजट से एक वार्षिक अवधि में भारतीय रेलवे से संबंधित अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का आकलन है वस्तुतः यह एक प्रमुख नीतिगत दस्तावेज है जिसका उपयोग भारतीय रेलवे के विकास से संबंधित कार्यक्रमों और सरकार सरकार की पहल का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने हेतु किया जाता है।

भारतीय रेल बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य :- Important facts about Indian Rail Budget :-

- यह एक विशेष बजट है जो आम बजट से बिल्कुल अलग है सर्वप्रथम 20 सदस्यीय एकवॉथ समिति की अनुशंसा पर 1924 में इसे पेश किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा 1921 में रेलवे के प्रदर्शन में सुधार के लिए रेल बजट की अनुशंसा की गई

- यह लोकसभा में धन विधेयक के रूप में केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
- आमतौर पर यह बजट आम बजट से कुछ दिन पहले पेश किया जाता है इससे पिछले वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण भी किया जाता है।
- ममता बनर्जी रेल बजट पेश करने वाली पहली महिला रेल मंत्री है 2002 में उन्होंने रेल बजट प्रस्तुत किया।
- सुरेश प्रभु अंतिम रेल मंत्री है जिन्होंने 2016 में अंतिम बार रेल बजट पेश किया।

* बजट प्रक्रिया
Budget Process

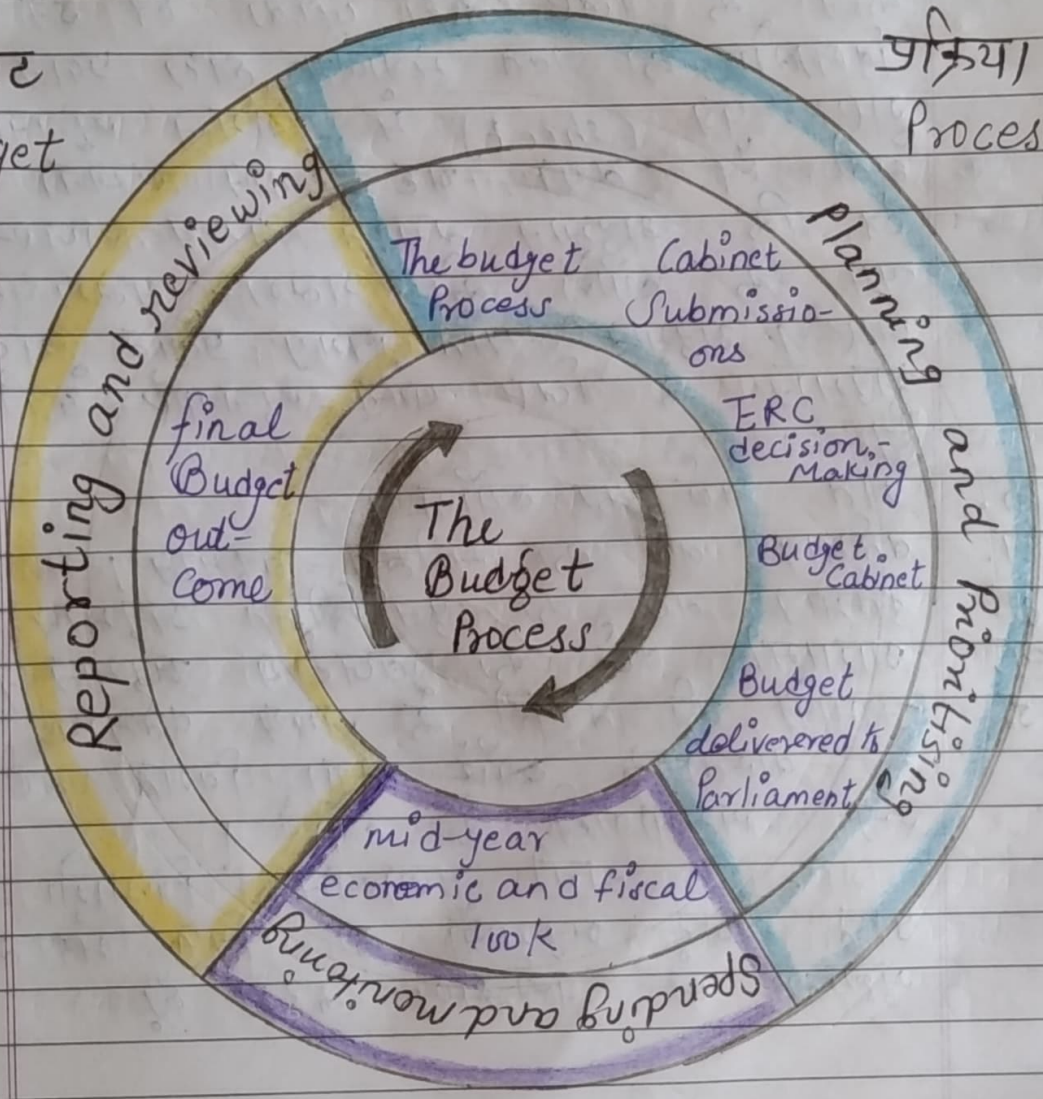

* भारत में बजट निर्माण का मुख्य उत्तरदायित्व कार्यपालिका के हाथों में होता है तथा बजट निर्माण की प्रक्रिया आगामी वित्त वर्ष से 7-8 महीने पहले से ही आरंभ हो जाती है वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों तथा विभागों को आगामी वर्ष का बजट तैयार करने हेतु एक पत्र भेजता है जिसमें सभी विभागों से अनुमानित राजस्व व व्यय का मदों को तैयार करने स्थानीय कार्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाते हैं तथा आगामी वर्ष के अपने विभागीय बजट को तैयार करने के लिए कहा जाता है इन सभी विभागों को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए पत्र (sheet) में विभिन्न सूचनाएं दी होती है तथा यह ध्यान रखना होता है कि अनुमान लगाते समय राजस्व व व्यय के ब्यौरों को अलग-अलग रखा जाए। अनुमान लगाते समय प्रत्येक मद के अनुमान के लिए पांच सूचनाएं दी होती है।-

क. गत वर्ष का ब्यौरा।
ख. वर्तमान वर्ष का स्वीकृत अनुमान।
ग. वर्तमान वर्ष का पुनर्निरीक्षित अनुमान।
घ. आगामी वर्ष का बजटीय अनुमान।
ङ. अनुमानों की तैयारी के समय वर्तमान वर्ष के वास्तविक ब्यौरे तथा विगत वर्ष में इस समयावधि के ब्यौरे।

सभी प्रशासनिक विभागों से प्राप्त बजट अनुमानों का वित्त मंत्रालय सूक्ष्मता से परीक्षण करता है

सभी बजट-विभागों के बजट अनुमानों को सामान्यतः - तीन भागों में विभक्त कर लिया जाता है। -

1. स्थायी प्रभार (व्यय) - इसके अन्तर्गत वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय तथा संस्थापना इत्यादि स्थायी व्यय सम्मिलित किये जाते हैं। बजट का लगभग आधा हिस्सा सरकारी तंत्र के रख-रखाव का वेतन भत्तों पर ही व्यय होता है।

2. प्रवर्तित कार्यक्रम या योजनाएँ :- इस भाग के अन्तर्गत निरन्तर वर्ष-दर-वर्ष जारी योजनाओं का व्यय सम्मिलित होता है। वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग प्रचलित योजनाओं की प्रगति, कुशलता तथा उपादेयता का समय-समय पर मूल्यांकन करता है तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का विश्लेषण भी करता है।

3. नये कार्यक्रम :- इस भाग में विभागों या सरकार द्वारा प्रस्तावित नये कार्यक्रमों के अनुमानित व्यय का आकलन किया जाता है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, योजना आयोग तथा अन्य विशेषज्ञ अभिकरणों से परामर्श लेता है क्योंकि नए कार्यक्रम या प्रस्ताव बजट पर बोझ बढ़ाते हैं। अतः सूक्ष्म परीक्षण आवश्यक है। वित्त मंत्रालय इस कार्य में संबंधित प्रशासनिक विभाग से निम्नांकित प्रश्न पूछता है -

- क्या प्रस्तावित व्यय वास्तव में आवश्यक है यदि हाँ, तो पूर्व में इसके बिना कैसे काम चलता था?
- उस प्रकार के व्ययों के संबंध में अन्य क्या व्यवस्था है?
- प्रस्तावित योजना में क्या-क्या कार्य होंगे तथा इसका धन कहाँ से आएगा?
- इस व्यय के परिणाम स्वरूप किसको धन का अभाव तुरन्त अनुभव होता?
- इस व्यय के परिणाम स्वरूप किसको धन का अभाव तुरन्त अनुभव होगा?
- क्या नये विकास कार्य इस व्यय को अनावश्यक बना सकते है?

* बजट के अनुमान के निर्माण में यह जानना अत्यंत आवश्यक है की वित्त मंत्रालय को इतनी अधिक शक्तियाँ क्यों प्रदान की गई है कि सभी विभागों के व्यय की मदों के लिए वित्त मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक है इसके दो कारण है प्रथम - वित्त मंत्रालय का कार्य धन का प्रबंधन करना है तथा वित्त मंत्रालय से यह अपेक्षा की जाती है कि कर दाताओं की राशि का सदुपयोग किया गया, तथा दूसरा वित्त मंत्रालय द्वारा ही यह तय किया जाता है कि प्रस्तावित व्यय के लिए धन का प्रबंध कैसे किया जाएगा इन कारणों से वित्त मंत्रालय को ही बजट अनुमान के निर्माण में विभिन्न विभागों पर अत्यधिक नियंत्रण की शक्तियां प्रदान की गई है।

* बजट निर्माण में संसद की भूमिका

→ बजट का प्रस्तुतीकरण :- बजट दो रूपों में पेश किया जाता है - रेल बजट तथा आम बजट। दोनों के लिए एक समान प्रक्रिया अपनायी जाती है। रेल बजट आम बजट से पहले पेश किया जाता है और आम बजट को वित्त मंत्री द्वारा फरवरी माह में अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है।

→ सामान्य चर्चा :- बजटीय भाषण के कुछ दिन की अवधि के पश्चात बजट पर सामान्य चर्चा आरंभ होती है। सामान्य चर्चा के दौरान बजट की सूक्ष्म मदों के संबंध में कोई टिप्पणी या चर्चा नहीं की जाती।

→ विभागीय समितियों द्वारा जाँच :- बजट पर सामान्य चर्चा के पश्चात सदनों को 3-4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस अंतराल में 16 विभागीय कार्यकारी समितियों द्वारा विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों की जांच की जाती है।

→ अनुदान की मांगों पर मतदान :- सामान्य चर्चा तथा विभागीय समितियों द्वारा अपनी रिपोर्ट देने के पश्चात लोकसभा में अनुदानों की मांगों पर मतदान का चरण आता है। प्रत्येक मांग को मंत्रालय के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

प्रस्ताव :- Three types of motion

- Policy cut motion
- economy cut motion
- Taken cut motion

→ विनियोग विधेयक :- लोकसभा द्वारा सभी मांगों पर मतदान करने के पश्चात उन सभी अनुदानों को संचित निधि पर भारित व्यय के साथ मिलाकर एक विधेयक के रूप में पेश किया जाता है।

→ लेखानुदान :- विनियोग विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात विनियोग अधिनियम बन जाता है तथा उसके पश्चात भारत की संचित निधि से राशि का आहरण किया जा सकता है

→ वित्त विधेयक :- विनियोग अधिनियम के पारित होने के साथ ही बजट को दो भागों से देखा जा सकता है। एक भाग व्यय से संबंधित है तथा दूसरा राजस्व तथा मुख्यतः करारोपण से संबंधित होता है।

* नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक - Comptroller and Auditor General - CAG

भारत में लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना सन 1853 में हुआ किंतु स्वतंत्र रूप से यह 1919 के एक्ट से स्थापित किया गया, जिसके कार्यों में वृद्धि 1935 के एक्ट के तहत की गई

* भारत में बजट प्रणाली सुधार :- एक निश्चित रूप से भारत जैसे नव स्वतंत्र और विकासशील अर्थव्यवस्था की जरूरत के लिए उपयुक्त नहीं है बजटीय प्रक्रिया में सुधार को हल आसीत सुधार के देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक उपकरण बनाने पर जोर दे रही है
यह सुनिश्चित करने के लिए की बजट प्रणाली सुधार देश के वित्तीय प्रशासन के सुधार

संचालन में किसी भी तरह की समस्या न बने, इसलिए इन सुधारों की प्रक्रिया के 3 अलग चरणों को भारत में पहचाना जा सकता है।

निष्कर्ष Conclusion

वित्त प्रशासन किसी भी देश को विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। वित्त प्रशासन का महत्वपूर्ण साधन बजट निर्माण व बजट का क्रियान्वयन है। बजट निर्माण का कार्य जनप्रतिनिधि के हाथों में दिया जाता है जिससे राजस्व को एकत्र करने व इसके प्रयोग में जनता के हितों का ध्यान रखा जाए। वित्त प्रशासन में बजट निर्माण प्रक्रिया में हितों का ध्यान रखा जाए। मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। बजट निर्माण व कार्यान्वयन के साथ ही बजट पर प्रभावी नियंत्रण भी आवश्यक है जिसके लिए महालेखा नियंत्रक व संसद की तीन मुख्य समितियाँ अहम भूमिका निभाती हैं।

भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया जिसमें विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष द्वारा सुझाये गये संरचनात्मक समायोजन अपनाया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में इन बदलावों इन परिणामस्वरूप राज्य ने अर्थव्यवस्था में अपनी मुखिया भूमिका को सीमित कर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया।